[2008] 17 एस.सी.आर. 572

एम/एस. कुमार एक्पोर्टस

बनाम

एम/एस शर्मा कार्पेट्स

(आपराधिक अपील संख्या 2045 आॅफ 2008)

16 दिसम्बर, 2008

[आर.वी. रवीन्द्रन और जे.एम. पंचाल, जे.जे.]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

धारा 118 और 139 - अनुमानों से संबंधित साक्ष्य के विशेष नियम, जब परक्राम्य लिखत विषय है - धारा 118 और 139 के तहत अनुमान - दायरा और सीमा - समझाया और स्पष्ट किया गया - साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा.3,4 और 114.

धारा 138 - चेक का अनादरण - रेस्पोंडेंट का मामला (शिकायतकर्ता) कि उसने अपीलकर्ता को कालीन बेचे और उक्त दायित्व के लिए उन्मोचन कर दिया, अपीलकर्ता ने चेक जारी किए जो अनादरित हो गये - अपीलकर्ता का बचाव है कि वह कालीन खरीदने के लिए सहमत

हुआ ओर एडवांस के तौर पर चेक जारी किये थे परंतु रेस्पोंडेंट ने कालीनों की आपूर्ति नहीं की - माना गया:

रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत बिल पर अपीलकर्ता की ओर से हस्ताक्षर नहीं थे - इसके विपरीत, बिक्री कर अधिकारी के अनुसार, यह स्पष्ट था कि रेस्पोंडेंट और अपीलकर्ता के बीच कालीनों की बिक्री का कोई लेन-देन नहीं हुआ- परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता पर कोई मौजूदा ऋण नहीं था जिसका भुगतान करने के लिए रेस्पोंडेंट को चेक जारी करने के लिए अपीलकर्ता से अपेक्षा की जावे - इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता का बचाव कि खाली चेक थे रेस्पोंडेंट द्वारा अग्रिम भुगतान के रूप में प्राप्त करना भी संभावित हो गया और बोझ का भार रेस्पोंडेंट पर स्थानांतरित हो गया - रेस्पोंडेंट ने कोई खाता-बही आदि प्रस्तुत नहीं की जिससे यह साबित होता हो कि उसके द्वारा अपीलकर्ता को कालीन बेचे गए थे - परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता बरी होने का हकदार है क्योंकि चेक धारक ने चेक किसी ऋण अथवा दायित्व के निर्वहन के लिए प्राप्त नहीं किये थे।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 386 - एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत - अभियुक्तगण का बरी होना - अपील - उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति को पलटना - सजा का उचित आदेश पारित करने के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट में भेजना - का औचित्य - माना गया:

उचित नहीं - उचित सजा देने का न्यायिक कार्य केवल अपीलीय न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है जब वह दोषमुक्ति के आदेश को उलट देता है न कि किसी अन्य अदालत द्वारा - यह उचित अधिरोपण करना उच्च न्यायालय का परम कर्तव्य था मामले के तथ्यों के अनुरूप, सजा - परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 - एस. 138.

अपीलकर्ता ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत मुकदमे का सामना किया। यह रेस्पोंडेंट का मामला था (शिकायतकर्ता) कि उसने ऊनी कालीन अभियुक्त-अपीलकर्ता को बेचे थे और उक्त दायित्व के निर्वहन में, अपीलकर्ता ने दो चेक जारी किए थे, जो थे अंततः अनादरित हो गये।

अपीलकर्ता का बचाव यह था कि वह रेस्पोंडेंट से ऊनी कालीन खरीदने के लिए सहमत हो गया था और अग्रिम के तौर पर चेक जारी किए लेकिन रेस्पोंडेंट ने कालीनों की आपूर्ति नहीं की।

ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को यह कहते हुए बरी कर दिया कि रेस्पोंडेंट द्वारा यह साबित नहीं किया गया कि अपीलकर्ता द्वारा किसी ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए चेक जारी किए गए थे। अपील पर, उच्च न्यायालय ने माना कि यदि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया बचाव सच होता तो उसके द्वारा चेकों का भुगतान' करने की अनुमति देने

के बजाय चेक का भुगतान रोकने के निर्देश दिये जाते बावजूद इसके चेकों को प्रस्तुत करने दिया गया और वे अनादरित हो गये आैर इस प्रकार अपीलकर्ता को बरी करने के आदेश को उलट दिया गया और उसके बाद मामले को ट्रायल कोर्ट को सजा का उचित आदेश पारित करने हेतु लौटाया गया। इस प्रकार वर्तमान अपील।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

माना गया :1.1. एक साधारण अनुबंध को लागू करने के मुकदमे में, वादी को अपनी दलील में यह बताना होगा कि यह किस लिए बनाया गया था प्रतिफलार्थ है और इसे साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करना चाहिए। लेकिन इस नियम के लिए, परक्राम्य लिखत एक अपवाद हैं। सामान्य नियम से एक महत्वपूर्ण विचलन में अनुबंधों पर लागू, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 118 अनुमानों से संबंधित साक्ष्यों के संबंध में कुछ विशेष नियम निर्धारित करता है। इन अनुमानों का कारण यह है कि, परक्राम्य लिखत से गुजरता है और समर्थन सौंपना होगा और इससे व्यापार होगा परक्राम्य लिखत की बहुत कठिन और परक्राम्यता असंभव, जब तक कि कुछ निश्चित धारणाएँ न बनाई जाएँ। इसलिए, अनुमान सुविधा के लिए सिद्धांत का विषय है बातचीत के साथ-साथ व्यापार भी। [पैरा 9] [581-जी-एच; 582-ए-सी]

1.2. अधिनियम की धारा 118 अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश देती है कि यह होगा जब तक विपरीत सिद्ध न हो जाए, तब तक यह माना जाता है कि प्रत्येक परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्थ बनाया या तैयार किया गया था। अधिनियम की धारा 139 यह निर्धारित करती है कि जब तक इसके विपरीत सिद्ध हो जाने पर यह मान लिया जाएगा कि चेक के धारक ने वह चेक धारा 138 में निर्दिष्ट किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में 'साबित' शब्द की परिभाषा अधिनियम की धारा 118 और 139 के प्रावधानों के अनुसार, यह बन जाता है स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 138 के तहत एक मुकदमे में एक अनुमान है प्रत्येक परक्राम्य लिखत बनाना होगा विचारार्थ बनाया या खींचा गया था और वह एक बार ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए निष्पादित परक्राम्य लिखत का निष्पादन या तो सिद्ध हो गया है या स्वीकार किया जा चुका है। जैसे ही शिकायतकर्ता यह साबित करने के बोझ से उन्मोचित हो जाता है कि परक्राम्य लिखत, एक नोट कहें, था अभियुक्त द्वारा निष्पादित, अनुमान के नियम अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत उसे साबित करने का भार आरोपी पर प्रतिस्थापित करने में मदद मिलती। धारणाएँ जीवित रहेंगी, अस्तित्व में रहेंगी और जीवित रहेगा और तभी समाप्त होगा जब विपरीत सिद्ध हो जाए अभियुक्त द्वारा, अर्थात् चेक जारी नहीं किया गया

था किसी भी ऋण या देनदारी पर विचार करना और उसका निर्वहन करना। एक अनुमान अपने आप में प्रमाण नहीं है, बल्कि केवल एक बनाता है प्रथम दृष्टया यह उस पक्ष के लिए मामला है जिसके लाभ के लिए यह अस्तित्व में है। [पैरा 10] [583-जी]

1.3. वाक्यांश का उपयोग "जब तक इसके विपरीत न हो।" अधिनियम की धारा 118 में सिद्ध किया गया है और शब्दों का प्रयोग किया गया है जब तक अधिनियम की धारा 139 में इसके विपरीत साबित होता है "मान सकते हैं" और "मानेंगे" की परिभाषाएँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में दिया गया, इसे तुरंत स्पष्ट कर देता है दोनों प्रावधानों के तहत अनुमान लगाए जाएंगे जो खंडन योग्य हैं। जब किसी अनुमान का खंडन किया जा सकता है, केवल तभी बताते हैं कि जिस पार्टी पर जाने का दायित्व है साक्ष्य के साथ अग्रेषित करें, अनुमानित तथ्य पर और कब उस पक्ष ने निष्पक्ष और उचित ढंग से साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं यह दिखाने की प्रवृत्ति है कि वास्तविक तथ्य वैसा नहीं है जैसा अनुमान लगाया गया था अनुमान का उद्देश्य समाप्त हो गया है। एक मुकदमे में अभियुक्त अधिनियम की धारा 138 के तहत दो विकल्प हैं। वह या तो कर सकता है दिखाएँ कि प्रतिफल और ऋण मौजूद नहीं थे या वह मामले की विशेष परिस्थितियों में गैर':" प्रतिफल और ऋण का अस्तित्व इतना संभावित है कि एक विवेकशील व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि कोई प्रतिफल और

कर्ज मौजूद था। वैधानिक अनुमानों का खंडन करने के लिए अभियुक्त से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह अपने आपराधिक मुकदमे से बचाव को इससे अधिक साबित कर सके उचित संदेह जैसा कि शिकायतकर्ता से अपेक्षित है। अभियुक्त प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है यह साबित करने के लिए कि विचाराधीन नोट था। प्रतिफल और यह कि उस पर कोई ऋण या देनदारी नहीं थी उसके द्वारा समर्थित नहीं है, छुट्टी दे दी गई। हालाँकि, अदालत को प्रत्येक मामले में इस पर ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है कि अभियुक्त द्वारा प्रतिफल और ऋण का अस्तित्व नहीं होने के संबंध में साक्ष्य क्योंकि नकारात्मक साक्ष्य का अस्तित्व न तो संभव है और न ही इस पर विचार किया गया है। [पैरा 11] (583-एच; 584- ए-ई]

1.4. साथ ही, गुजर जाने की बात से साफ इनकार किया जाहिरा तौर पर ऋण का विचार और अस्तित्व अभियुक्त का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कुछ जो संभावित है उसे प्राप्त करने के लिए रिकॉर्ड पर लाना होगा सबूत का भार शिकायतकर्ता पर स्थानांतरित कर दिया गया। अनुमानों का खंडन करने के लिए, अभियुक्त को सामने लाना चाहिए ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों को रिकॉर्ड पर लाया जाये जिस पर विचार करते हुए, अदालत या तो यह मान सकती है कि प्रतिफल और ऋण मौजूद नहीं थे या उनकी गैर- अस्तित्व इतना संभावित था कि एक विवेकशील व्यक्ति ऐसा कर सकता था मामले की परिस्थितियों के तहत, याचिका पर कार्रवाई करें कि

उनका अस्तित्व ही नहीं था। प्रत्यक्ष जोड़ने के अलावा यह साबित करने के लिए साक्ष्य कि विचाराधीन नोट नहीं था प्रतिफल द्वारा समर्थित या जो उसने खर्च नहीं किया था, किसी ऋण या देनदारी पर भी अभियुक्त भरोसा कर सकता है परिस्थितिजन्य साक्ष्य और यदि परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिन पर भरोसा करना बाध्यकारी है, साबित करने का भार फिर से शिकायतकर्ता के पास उसी तरह बदल सकता है। आरोपी भी भरोसा कर सकता है उदाहरण के लिए, तथ्य की धारणाओं पर, जिनका उल्लेख किया गया है अनुमानों का खंडन करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 में अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत उत्पन्न होने वाली। आरोपी के पास है के अस्तित्व में न होने को सिद्ध करने का भी एक विकल्प प्रतिफल और ऋण या देनदारी या तो किराये पर देकर साक्ष्य या कुछ स्पष्ट और असाधारण मामलों में, से शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामला, अर्थात् कथन सी शिकायत में, मामला वैधानिक नोटिस में निर्धारित किया गया है और शिकायतकर्ता द्वारा इस दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य परीक्षण। एक बार इस तरह के खंडन साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए जाएं और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया मामले की परिस्थितियाँ और उसकी प्रबलता डी संभावनाएं, साक्ष्य का बोझ वापस स्थानांतरित हो जाता है शिकायतकर्ता और उसके बाद, नीचे दी गई धारणाएँ अधिनियम की धारा 118 और 139 फिर से

लागू नहीं होगी शिकायतकर्ता का बचाव। [पैरा 11] [584-एफ-एच; 585-ए-सी]

2.1. वर्तमान मामले में, अपने मामले के समर्थन में, ई रेस्पोंडेंट ने बिल की कार्बन कॉपी प्रस्तुत की। एक विधेयक के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है रेस्पोंडेंट द्वारा किया गया समर्थन स्वीकार करते हुए बिल की सामग्री की शुद्धता। बिल न तो अपीलकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है। इसके विपरीत, अपीलकर्ता ने बिक्री कर विभाग के एक अधिकारी से पूछताछ की, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सकारात्मक रूप से कहा कि रेस्पोंडेंट ने मूल्यांकन के लिए बिक्री कर रिटर्न दाखिल किया था वर्ष 1994-95 ऊनी कालीनों की बिक्री न होने का संकेत उक्त मूल्यांकन वर्ष के दौरान हुआ था और इसलिए बिक्री कर का भुगतान नहीं किया गया। उक्त गवाह भी रेस्पोंडेंट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया यह दर्शाता है कि वर्ष 1994-95 के दौरान कोई बिक्री नहीं हुई थी रेस्पोंडेंट द्वारा ऊनी कालीनों का यद्यपि शिकायतकर्ता को जिरह करने का पर्याप्त अवसर दिया गया- उक्त गवाह की जांच करें, कुछ भी पता नहीं चल सका अपनी जिरह के दौरान ताकि उसके बारे में संदेह पैदा किया जा सके। उनका दावा है कि ऊनी कालीनों की बिक्री का कोई लेन-देन नहीं हुआ, वर्ष 1994-95 के दौरान रेस्पोंडेंट द्वारा प्रभावित किया गया था। [पैरा 12] [585-ई-एच; 586-ए]

2.2. एक बार सेल्स टैक्स के अधिकारी की गवाही विभाग ने स्वीकार कर लिया है, इससे स्पष्ट नहीं हो जाता है कि रेस्पोंडेंट और अपीलकर्ता के बीच ऊनी कालीनों की बिक्री का लेन-देन हो चुका था, जैसा कि रेस्पोंडेंट पर आरोप लगाया गया है। जब ऊनी कालीनों की बिक्री नहीं होती थी हो गया, भुगतान हेतु कोई मौजूदा ऋण नहीं था रेस्पोंडेंट को अपीलकर्ता से चेक जारी करने की अपेक्षा की गई थी। इस प्रकार अभियुक्त ने आरोपमुक्त कर दिया है यह साबित करने की जिम्मेदारी कि चेक प्राप्त नहीं हुए थे किसी ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए धारक। नीचे परिस्थितियों में अपीलकर्ता का बचाव रिक्त है रेस्पोंडेंट द्वारा अग्रिम के रूप में चेक प्राप्त किये गये थे भुगतान भी संभव हो जाता है और भार भी बढ़ जाता है जो शिकायतकर्ता पर शिफ्ट होगा। शिकायतकर्ता ने नहीं किया कोई भी खाता बही या स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत करें अपने नियमित व्यवसाय के दौरान उनके द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है या माल की डिलीवरी के लिए कोई पावती स्थापित करें कि वास्तव में ऊनी कालीन थे उसके द्वारा अपीलकर्ता को राशि के बदले बेच दिया गया। रेस्पोंडेंट को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड पर सामग्री, अधिनियम की धारा 138 के तहत उसका मामला स्थापित करने में विफल रही । जो निर्णय सुनाया गया उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को धारा 138 के तहत दोषी ठहराया गया इसलिए अधिनियम को रद्द किया जाता है और निर्णय सुनाया जाता

है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थी को बरी करते हुए, बहाल कर दिया गया है. [पैरा 12 और 14] [586-ए-ई; 587-डी-ई]

3. इसके अलावा हाई कोर्ट ने दोषी करार देने के बाद अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 138 के तहत मामले को वापस भेज दिया सजा का उचित आदेश पारित करने के लिए मजिस्ट्रेट। जी उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए इस पाठ्यक्रम के बारे में अज्ञात है कानून। के एक आदेश की अपील पर सुनवाई हो रही थी दोषमुक्ति अपील में अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ दोषमुक्ति के आदेश से, की धारा 386(ए) में गिना गया है दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973। वे शक्तियाँ ऐसा करती हैं रिकॉर्डिंग के बाद अपीलीय न्यायालय पर विचार न करें दोषसिद्धि के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट में भेजा जा सकता है सजा का उचित आदेश पारित करना। न्यायिक उचित सज़ा लगाने का कार्य हो सकता है केवल अपीलीय न्यायालय द्वारा ही निष्पादित किया जाता है जब। यह उलट जाता है बरी करने का आदेश, किसी अन्य न्यायालय द्वारा नहीं। होना बी दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के संबंध में, 1973, की धारा 138 के तहत अपीलकर्ता को दोषी पाते हुए अधिनियम, उचित लगाने का न्यायिक विवेक उच्च द्वारा सजा को रद्द नहीं किया जा सकता था कोर्ट मजिस्ट्रेट के पक्ष में. पाकर सी अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी है, यह बाध्यता थी उचित सजा देना उच्च न्यायालय का कर्तव्य है मामले के तथ्यों के अनुरूप. इसलिए

उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया नहीं हो सकती स्वीकृत या स्वीकार किया हुआ। [पैरा 13] [586-एफ-एच; [587-ए-बी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 2045/2008।

अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 1.2.2007 से और 23.11.2006 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की चंडीगढ़ सीआरएल में। एम.सी. आपराधिक अपील में 2007 की संख्या 5155-56/2004 की संख्या 946-एसबीए और आपराधिक अपील संख्या 946-एसबीए क्रमशः 2004.

के.सी. बजाज, संजीव मल्होत्रा, हिमांशु बजाज और प्रदीप अपीलकर्ता की ओर से शुक्ला।

नरेश कौशिक, मनीष कौशिक, अर्निता कलकल और ललिता रेस्पोंडेंट की ओर से नरेश कौशिक।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

जे.एम. पंचाल, जे. 1. छुट्टी स्वीकृत।

2. त्वरित अपील दिनांकित निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है जी नवंबर 23, 2006, के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रतिपादित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, आपराधिक अपील संख्या 946 में 2004 का

एसबीए, जिसके द्वारा निर्णय दिनांक 6 दिसंबर 2003, में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कमल द्वारा पारित किया गया 2001 की आपराधिक शिकायत संख्या 178, अपीलकर्ता को बरी कर देती है एच परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत ('संक्षेप में अधिनियम') अपीलकर्ता को दोषी ठहराए जाने के बाद रद्द कर दिया जाता है अधिनियम की धारा 138 के तहत मामले को प्रेषित किया जाता है विद्वान मजिस्ट्रेट सजा का उचित आदेश पारित करें।

3. जय भगवान शर्मा, मैसर्स के मालिक। शर्मा यहां रेस्पोंडेंट, कालीन, कालीन का व्यापार करता है। राजिंदर कुमार, मिस के मालिक। कुमार एक्सपोर्ट्स, यहां अपीलकर्ता, पानीपत में कारोबार कर रहा है। का मामला है रेस्पोंडेंट ने कहा कि अपीलकर्ता ने हाथ से बने ऊनी कपड़े खरीदे 6 अगस्त 1994 को उनसे कालीन, जिसकी कीमत थी 1,90,348.39 रुपये रेस्पोंडेंट, अपीलकर्ता के अनुसार दो चेक जारी किए, यानी एक चेक जिसका नंबर 052912 है। 1,00,000/- रुपये की राशि के लिए दिनांक 25 अगस्त 1994 और अन्य चेक क्रमांक 052913 दिनांक 25 सितंबर 1994 यूनियन की पानीपत शाखा पर 90,348.39 रुपये की राशि निकाली गई बैंक ऑफ इंडिया, अपनी देनदारी के निर्वहन के लिए। का मामला रेस्पोंडेंट का कहना है कि चेक बैंक में जमा किये गये थे उन्हें नकदीकरण के लिए भेजा गया था, लेकिन वे चेक वापस मिल गये "अपर्याप्त धनराशि" टिप्पणी के साथ

अवैतनिक। का मामला है रेस्पोंडेंट का कहना था कि तथ्य यह है कि चेक बाउंस हो गए थे अपर्याप्त धनराशि को अपीलकर्ता के ध्यान में लाया गया और अपीलकर्ता के अनुरोध पर पुनः चेक दिये गये 5 जनवरी 1995 को बैंक में नकदीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया, परन्तु खाते में धनराशि न होने के कारण उन्हें फिर से अपमानित होना पड़ा अपीलकर्ता की फर्म का. रेस्पोंडेंट द्वारा क्या दावा किया गया है यह है कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने वैधानिक नोटिस दिया था दिनांक 19 जनवरी, 1995 को अपीलकर्ता को बनाने के लिए कहा गया देय राशि का भुगतान लेकिन अपीलकर्ता ने कोई जवाब नहीं दिया उक्त नोटिस न ही देय राशि का भुगतान किया। इसलिए, रेस्पोंडेंट ने 2001 की आपराधिक शिकायत संख्या 178 दायर की विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कमल की अदालत में और अपीलकर्ता को धारा 138 के तहत दोषी ठहराने की प्रार्थना की कार्यवाही करना।

4. समन की तामील पर अपीलकर्ता समक्ष उपस्थित हुआ कोर्ट। उनका बचाव यह था कि जो बिल पेश किया गया रेस्पोंडेंट ने ऊनी कालीनों की बिक्री को फर्जी बताया एक और उसके हस्ताक्षर वाले खाली चेक ले लिए गए रेस्पोंडेंट द्वारा उसे खरीदने में सक्षम बनाने के लिए उसके लिए कच्चा माल। अपीलकर्ता के अनुसार चेक की आपूर्ति के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में थे कालीन, लेकिन रेस्पोंडेंट सामान पहुंचाने में विफल

रहा था उसे। अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि रेस्पोंडेंट ने रोक दिया था कालीन निर्माण और चूंकि चेक जारी नहीं किए गए थे अधिनियम की धारा 138 के तहत 8 किसी भी दायित्व के निर्वहन के बाद, वह दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं था।

5. अपने मामले को साबित करने के लिए रेस्पोंडेंट ने परीक्षण किया खुद को सीडब्ल्यू-3 बताया और चेक अनादरित किए गए पूर्व। सीडब्ल्यू-2/ए और सीडब्ल्यू-2/बी, पूर्व में वैधानिक सूचना। सी-4, कार्बन सीडब्ल्यू-2/सी आदि पर बिल की प्रति। उन्होंने दो गवाहों से पूछताछ की सी चेक की प्रस्तुति और अनादर को साबित करें। अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायत में कोई अन्य नहीं अपने मामले के समर्थन में उनके द्वारा गवाहों से परीक्षण किया गया। अपीलार्थी ने परीक्षण किया स्वयं अपने बचाव को डीडब्ल्यू-1 के रूप में प्रमाणित करने के लिए। वह भी सेल्स में क्लर्क के रूप में कार्यरत श्री ओम प्रकाश की जांच की गई डी कर विभाग, डीडब्ल्यू-2 के रूप में, जिसने न्यायालय के समक्ष यह कहा रेस्पोंडेंट की फर्म ने बिक्री कर रिटर्न दाखिल किया था निर्धारण वर्ष 1994-95 घोषित करता है कि कोई बिक्री या खरीद नहीं ऊनी कालीनों की बिक्री हुई थी और इसलिए, कोई बिक्री कर नहीं था जमा कर दिया गया। उक्त गवाह ने एक शपथ पत्र भी दाखिल किया रेस्पोंडेंट द्वारा जिसको प्रदर्श डी-1 के रूप में दर्शाया गया

है जिसमें रेस्पोंडेंट के पास था शपथपूर्वक कहा गया कि ऊनी कालीनों की कोई बिक्री या खरीद नहीं होगी निर्धारण वर्ष 1994-95 के दौरान हुआ।

6. विद्वान मजिस्ट्रेट ने साक्ष्य की सराहना की कि चेकों का निष्पादन अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया था एफ और यह रेस्पोंडेंट द्वारा साबित किया गया था कि वे जाँच करते हैं अपर्याप्त धनराशि के कारण अनादरित किया गया। हालांकि विद्वान मजिस्ट्रेट ने निष्कर्ष निकाला कि यह साबित नहीं हुआ रेस्पोंडेंट ने कहा कि चेक अपीलकर्ता द्वारा जारी किए गए थे किसी ऋण या दायित्व का निर्वहन। विद्वान मजिस्ट्रेट ने देखा जी कि बिल पूर्व में प्रस्तुत किया गया। सीडब्ल्यू-2/सी पर हस्ताक्षर नहीं थे खरीदार के रूप में अपीलकर्ता को इसकी स्वीकृति स्वीकार करनी होगी या शुद्धता. विद्वान मजिस्ट्रेट ने यह भी नोट किया कि नंबर खाता-बही के रूप में पुष्टिकारक साक्ष्य थे रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया और इसलिए, यह संदिग्ध था क्या वास्तव में रेस्पोंडेंट ने कोई सामान पहुंचाया था अपीलकर्ता विद्वान मजिस्ट्रेट ने गवाही का उल्लेख किया बिक्री कर विभाग से गवाह और निष्कर्ष निकाला कि के रूप में द्वारा ऊनी कालीनों की बिक्री का कोई लेन-देन नहीं किया गया निर्धारण वर्ष 1994-95 के दौरान रेस्पोंडेंट, बचाव अपीलकर्ता द्वारा निवेदन किया गया था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए उल्लिखित निष्कर्षों पर, विद्वान मजिस्ट्रेट ने बरी कर दिया 6 दिसंबर 2003 के निर्णय द्वारा अपीलकर्ता।

7. व्यथित महसूस करते हुए, रेस्पोंडेंट ने अपराधी को प्राथमिकता दी पंजाब उच्च न्यायालय में 2004 की अपील संख्या 946 एसबीए और हरियाणा, चंडीगढ़। विद्वान एकल न्यायाधीश, जिसने अपील की सुनवाई की। एक की राय थी कि धारा 139 के संदर्भ में अधिनियम में यह धारणा थी कि चेक द्वारा प्राप्त किया गया रेस्पोंडेंट किसी ऋण या दायित्व के निर्वहन के पक्ष में थे चेकों के निष्पादन में अपीलार्थी को वहन करना पड़ा अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया और अपीलकर्ता ने स्थान नहीं दिया ऐसी धारणा का खंडन करने के लिए सामग्री जिसके परिणामस्वरूप, वह था अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि यदि बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया अपीलकर्ता सच था, उसने 'रोकने' के निर्देश जारी कर दिए होते चेकों का भुगतान करने की अनुमति देने के बजाय प्रस्तुत किया गया और अनादरित किया गया। उनका यह भी विचार था कि, शिकायतकर्ता (यहां अपीलकर्ता) का हलफनामा कि कोई ई नहीं था 1994-95 के दौरान लेनदेन, एक प्रासंगिक परिस्थिति नहीं थी। तदनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया अधिनियम की धारा 138 के तहत मामले को सुनवाई के लिए भेज दिया गया सुनवाई के बाद सजा का उचित आदेश पारित करने के लिए अदालत अपीलकर्ता और रेस्पोंडेंट व्यथित महसूस

करते हुए, अपीलकर्ता ने तत्काल दाखिल करके इस न्यायालय से संपर्क किया है निवेदन।

8. हमने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना और मामले के रिकॉर्ड पर विचार किया।

9. प्रश्न का निर्धारण करने के लिए कि क्या अपराध है के विरूद्ध अधिनियम की धारा 138 के तहत दण्डनीय अपराध बनता है अपीलकर्ता को दायरे की जांच करना आवश्यक होगा और द्वारा परिकल्पित अनुसार अनुमानों का दायरा बढ़ाया जाना है अधिनियम की धारा 118 और 139 के प्रावधान। एक सूट में एक साधारण अनुबंध लागू करें, वादी को अपना पक्ष रखना होगा यह दलील देते हुए कि यह अच्छे विचार के लिए बनाया गया है और अवश्य बनाया जाना चाहिए साक्ष्य द्वारा इसकी पुष्टि करें। लेकिन इस नियम के लिए, परक्राम्य उपकरण अपवाद हैं। महत्वपूर्ण प्रस्थान में सुनवाई अनुबंधों पर लागू सामान्य नियम, अधिनियम की धारा 118 उठाए जाने वाले कुछ अनुमान प्रदान करता है। यह अनुभाग रखता है अनुमानों से संबंधित साक्ष्य के कुछ विशेष नियम नीचे दिए गए हैं। इन धारणाओं का कारण यह है कि, परक्राम्य लिखत समर्थन एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाता है और यह बनेगा व्यापार करना अत्यंत कठिन और साधन की परक्राम्यता असंभव, जब तक कि कुछ निश्चित धारणाएँ न बनाई जाएँ।

इसलिए, अनुमान सुविधा के लिए सिद्धांत का विषय है बातचीत के साथ-साथ व्यापार भी। अधिनियम की धारा 118 प्रदान करती है जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए तब तक अनुमान लगाए जाएं (i) जैसा कि विचार, (ii) लिखत की तिथि के संबंध में, (iii) समय के संबंध में स्वीकृति, (iv) स्थानांतरण के समय के संबंध में, (v) आदेश के संबंध में पृष्ठांकन, (vi) उपयुक्त स्टाम्प के रूप में और (vii) धारक के रूप में नियत समय में धारक होना। अधिनियम की धारा 139 प्रदान करती है यह माना जाएगा, जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए चेक धारक को संदर्भित प्रकृति का चेक प्राप्त हुआ धारा 138 में किसी को पूर्णतः या आंशिक रूप से उन्मुक्त करने के लिए ऋण या अन्य दायित्व। अनुमान ऐसे उपकरण हैं जिनके उपयोग से अदालतें सक्षम हैं और किसी मुद्दे पर फैसला सुनाने की हकदार हैं इसके बावजूद कि कोई सबूत नहीं है या अपर्याप्त है प्रमाण। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सभी धारणाएं होनी चाहिए तीनों वर्गों में से किसी न किसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं अधिनियम में उल्लेख किया गया है, अर्थात्, (1) "मान सकते हैं" (खंडन योग्य), (2) "मानेंगे" (खंडन योग्य) और (3) "निर्णायक"। अनुमान" (अकाट्य)। 'अनुमान' शब्द का प्रयोग किया जाता है एक अनुमान निर्दिष्ट करें, सकारात्मक या अपुष्ट अस्तित्व एक तथ्य है, जिसे आसानी से "अनुमानित तथ्य" कहा जाता है एक न्यायिक न्यायाधिकरण द्वारा, संभावित तर्क की एक प्रक्रिया द्वारा कोई

तथ्यात्मक मामला, या तो न्यायिक रूप से देखा गया या स्वीकार किया गया या न्यायाधिकरण की संतुष्टि के लिए कानूनी साक्ष्य द्वारा स्थापित। अनुमान का शाब्दिक अर्थ है "बिना परीक्षण के सत्य मान लेना।" या प्रमाण'. साक्ष्य अधिनियम की धारा:4 अन्य बातों के साथ-साथ परिभाषित करती है। शब्द 'अनुमान लगा सकते हैं' और 'निम्नानुसार अनुमान लगाएंगे: -

> "(ए) 'धारणा कर सकता है' - जब भी यह इस अधिनियम द्वारा प्रदान किया जाता है कि न्यायालय किसी तथ्य को मान सकता है, वह ऐसा भी कर सकता है ऐसे तथ्य को तब तक सिद्ध मानें जब तक वह सिद्ध न हो जाए अस्वीकृत किया गया है या इसका प्रमाण मांगा जा सकता है।
>
> (बी) 'धारणा करेगा' - जब भी यह इस अधिनियम द्वारा निर्देशित हो कि न्यायालय एक तथ्य पर विचार करेगा, वह इस पर विचार करेगा ऐसा तथ्य जब तक सिद्ध न हो जाए अस्वीकृत।"

पहले मामले में न्यायालय के पास इसे बढ़ाने का विकल्प है अनुमान हो या न हो, लेकिन बाद वाले मामले में, न्यायालय को ऐसा करना ही होगा आवश्यक रूप से अनुमान बढ़ाएँ। यदि किसी मामले में न्यायालय ने

अनुमान को बढ़ाने और अनुमान को बढ़ाने का एक विकल्प, अनुमानों की दो श्रेणियों के बीच अंतर समाप्त हो जाता है और तथ्य मान लिया जाता है, जब तक कि ऐसा न हो अस्वीकृत

10. अधिनियम की धारा 118 अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश देती है कि ऐसा होगा जब तक विपरीत साबित न हो जाए, तब तक यह मान लिया जाता है कि हर चीज़ परक्राम्य है विचारार्थ उपकरण बनाया या तैयार किया गया था। धारा 139 अधिनियम में प्रावधान है कि जब तक विपरीत साबित न हो जाए, ऐसा होगा मान लिया जाए कि चेक धारक को प्राप्त हो गया है किसी भी ऋण के संपूर्ण या आंशिक भुगतान के लिए चेक देयता। 'सिद्ध' शब्द की परिभाषा को लागू करते हुए जन अनुभाग साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के प्रावधानों के लिए 3 और अधिनियम की धारा 139, यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा के तहत एक मुकदमे में अधिनियम की धारा 138 में यह धारणा बनानी होगी कि प्रत्येक परक्राम्य लिखत तैयार कर लिया गया था या विचार के लिए तैयार कर लिया गया था और यह कि इसे एक बार ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए निष्पादित किया गया था परक्राम्य लिखत का निष्पादन या तो प्रमाणित है या स्वीकार किया. जैसे ही शिकायतकर्ता बोझ उतारता है यह साबित करने के लिए कि उपकरण, मान लीजिए एक नोट, द्वारा निष्पादित किया गया था अभियुक्त, धारा 118 के तहत अनुमान के नियम और अधिनियम की धारा 139 उसे

आरोपी पर बोझ डालने में मदद करती है। धारणाएँ जीवित रहेंगी, अस्तित्व में रहेंगी और जीवित रहेंगी और तभी समाप्त होंगी अभियुक्त द्वारा इसके विपरीत सिद्ध किया गया है अर्थात् चेक किया गया था विचारार्थ और किसी ऋण के निर्वहन के लिए जारी नहीं किया गया है देयता। एक अनुमान अपने आप में प्रमाण नहीं है, बल्कि केवल बनाता है यह उस पक्ष के लिए प्रथम दृष्टया मामला है जिसके लाभ के लिए यह अस्तित्व में है।

11. "जब तक विपरीत सिद्ध न हो जाए" वाक्यांश का प्रयोग अधिनियम की धारा 118 और शब्दों का प्रयोग "जब तक विपरीत साबित होता है" अधिनियम की धारा 139 के साथ पढ़ें जैसा कि इसमें दिया गया है, "अनुमान लगा सकता है" और "अनुमान लगाएगा" की परिभाषाएँ दी गई हैं साक्ष्य अधिनियम की धारा 4, इसे तुरंत स्पष्ट कर देती है दोनों प्रावधानों के तहत उठाए जाने वाले अनुमान हैं खंडनयोग्य. जब किसी अनुमान का खंडन किया जा सकता है, तो यह केवल इंगित करता है कि जिस पार्टी पर आगे बढ़ने की जिम्मेदारी है सबूत, तथ्य पर अनुमान लगाया गया है और उस पक्ष ने कब किया है यह दिखाने के लिए निष्पक्ष और उचित रूप से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए वास्तविक तथ्य वैसा नहीं है जैसा अनुमान लगाया गया था, अनुमान का उद्देश्य खत्म हो गया है। अधिनियम की धारा 138 के तहत एक मुकदमे में आरोपी है दो विकल्प। वह या तो उस प्रतिफल और ऋण को दिखा सकता है अस्तित्व में नहीं था

या कि विशेष परिस्थितियों में प्रतिफल और ऋण के न होने की स्थिति में ऐसा होता है संभव है कि एक विवेकशील व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि नहीं प्रतिफल और ऋण विद्यमान थे। वैधानिक खंडन करने के लिए अनुमान है कि किसी अभियुक्त से अपने बचाव को साबित करने की उम्मीद नहीं की जाती है उचित संदेह से परे, जैसा कि एक आपराधिक मुकदमे में शिकायतकर्ता से अपेक्षा की जाती है। अभियुक्त प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है साबित करें कि विचाराधीन नोट समर्थित नहीं था प्रतिफल और यह कि उस पर कोई ऋण या देनदारी नहीं थी उसके द्वारा छुट्टी दे दी गई। हालाँकि, अदालत को हर मामले में इस बात पर ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है कि अभियुक्त को अस्तित्व में न होने का खंडन करना चाहिए प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करके प्रतिफल और ऋण क्योंकि नकारात्मक साक्ष्य का अस्तित्व न तो संभव है और न ही चिंतन किया. साथ ही, यह स्पष्ट है कि इसका नंगा खंडन किया गया है प्रतिफल का पारित होना और ऋण का अस्तित्व, जाहिर तौर पर इससे आरोपी का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जो कुछ संभावित है उसे रिकॉर्ड पर लाना होगा सबूत का भार शिकायतकर्ता पर डाल दिया जाना। को अनुमानों का खंडन करें, आरोपी को रिकॉर्ड पर लाना चाहिए ऐसे तथ्य एवं परिस्थितियाँ, जिन पर विचार करने पर अदालत या तो यह मान सकती है कि प्रतिफल और ऋण नहीं था उनका अस्तित्व हो या न हो, इसकी संभावना इतनी थी कि एक

विवेकशील व्यक्ति मामले की परिस्थितियों के तहत, याचिका पर कार्यवाही की जाएगी थाल वे अस्तित्व में नहीं थे। प्रत्यक्ष साक्ष्य जोड़ने के अलावा साबित करें कि विचाराधीन नोट समर्थित नहीं था प्रतिफल या कि उस पर कोई ऋण या देनदारी नहीं थी, अभियुक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भी भरोसा कर सकता है और यदि जिन परिस्थितियों पर इस प्रकार भरोसा किया गया है वे मजबूर करने वाली हैं, बोझ हैं इसी तरह फिर से शिकायतकर्ता पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अभियुक्त उदाहरण के लिए, तथ्य की धारणाओं पर भी भरोसा किया जा सकता है इसका खंडन करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 में उल्लेख किया गया है अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत उत्पन्न होने वाली धारणाएँ। आरोपी के पास अस्तित्व में न होने को साबित करने का भी विकल्प है प्रतिफल और ऋण या देनदारी या तो साक्ष्य देकर या कुछ स्पष्ट और असाधारण मामलों में, निर्धारित मामले से शिकायतकर्ता द्वारा, अर्थात, शिकायत में दिए गए कथन वैधानिक नोटिस और प्रस्तुत साक्ष्य में मामला निर्धारित किया गया है सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता। एक बार ऐसे खंडन प्रमाण सभी को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय द्वारा प्रस्तुत और स्वीकार किया जाता है मामले की परिस्थितियाँ और उसकी प्रबलता संभावनाएँ, साक्ष्य का बोझ वापस स्थानांतरित हो जाता है शिकायतकर्ता

और, उसके बाद, धाराओं के तहत अनुमान अधिनियम की धारा 118 और 139 फिर से शिकायतकर्ता के बचाव में नहीं आएंगी।

12. अपीलकर्ता का बचाव यह था कि वह सहमत था रेस्पोंडेंट से ऊनी कालीन खरीदने के लिए और उसके पास था अग्रिम के रूप में चेक जारी किए और रेस्पोंडेंट को कालीनों की आपूर्ति नहीं की। यह का विशिष्ट मामला है रेस्पोंडेंट ने कहा कि उसने अपीलकर्ता को ऊनी कालीन बेचे थे 6.8.1994 को और अपीलकर्ता ने उक्त दायित्व का निर्वहन किया ने दो चेक जारी किए थे, जो अंततः अनादरित हो गए। अपने मामले के समर्थन में रेस्पोंडेंट ने कार्बन प्रस्तुत किया बिल की प्रति. विधेयक के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है को स्वीकार करने वाले रेस्पोंडेंट द्वारा कोई समर्थन नहीं किया गया है बिल की सामग्री की शुद्धता बिल पर न तो हस्ताक्षर हैं अपीलकर्ता द्वारा इसके विपरीत, अपीलकर्ता ने एक की जांच की बिक्री कर विभाग के अधिकारी, जिन्होंने सकारात्मक रूप से दावा किया अदालत के समक्ष कि रेस्पोंडेंट ने बिक्री कर रिटर्न दाखिल किया था निर्धारण वर्ष 1994-95 के लिए यह दर्शाता है कि कोई बिक्री नहीं उक्त मूल्यांकन के दौरान ऊनी कालीनों का उपयोग किया गया था, वर्ष और, इसलिए, बिक्री कर का भुगतान नहीं किया गया था। उक्त गवाह रेस्पोंडेंट द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1994-95 के दौरान ऊनी कपड़ों की कोई बिक्री नहीं हुई रेस्पोंडेंट द्वारा कालीन हालांकि शिकायत दी गई थी उक्त

गवाह से जिरह करने का पर्याप्त अवसर, कुछ नहीं उसकी जिरह के दौरान पता लगाया जा सकता है ताकि सृजन किया जा सके उनके इस दावे पर संदेह है कि ऊनी कपड़ों की बिक्री का कोई लेन-देन नहीं हुआ वर्ष 1994 के दौरान रेस्पोंडेंट द्वारा कालीनों का निर्माण किया गया था। एक बार बिक्री कर अधिकारी की गवाही विभाग स्वीकार कर लिया है, यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई लेन-देन नहीं है के बीच ऊनी कालीनों की जमकर बिक्री हुई रेस्पोंडेंट और अपीलकर्ता, जैसा कि रेस्पोंडेंट ने आरोप लगाया है। जब ऊनी कालीनों की बिक्री नहीं होती थी, तब होती थी अपीलकर्ता पर कोई मौजूदा ऋण नहीं था जिसका भुगतान किया जा सके रेस्पोंडेंट को चेक जारी करने की उम्मीद है। इस प्रकार आरोपी यह साबित करने की जिम्मेदारी से मुक्त हो गया है कि चेक नहीं थे किसी ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए धारक द्वारा प्राप्त किया गया। अंतर्गत परिस्थितियों में अपीलकर्ता का बचाव रिक्त है रेस्पोंडेंट द्वारा अग्रिम के रूप में चेक प्राप्त किये गये थे भुगतान भी संभव हो जाएगा और बोझ भी बढ़ेगा शिकायतकर्ता पर शिफ्ट करें। शिकायतकर्ता ने कोई प्रस्तुत नहीं किया उसके द्वारा बनाए गए खाते की किताबें या स्टॉक रजिस्टर उसके नियमित व्यवसाय के दौरान या उसके लिए कोई पावती माल की डिलीवरी, इसे वास्तव में ऊनी के रूप में स्थापित करने के लिए 6 अगस्त 1994 को उनके द्वारा अपीलकर्ता को कालीन बेचे गए थे 1,90,348.39 रुपये की राशि के लिए। सामग्री को

ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड, इस न्यायालय की राय है कि रेस्पोंडेंट विफल रहा आवश्यकतानुसार अधिनियम की धारा 138 के तहत अपना मामला स्थापित करने के लिए कानून द्वारा और, इसलिए, उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय अलग रखे जाने योग्य है.।

13. इस कोर्ट ने एक अजीब और बेहद अजीब बात भी नोटिस की है परेशान मामले की विशेषता. हाई कोर्ट ने दोषी करार देने के बाद अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 138 के तहत मामले को माफ कर दिया उचित आदेश पारित करने के लिए विद्वान मजिस्ट्रेट को वाक्य। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया यह पाठ्यक्रम, कानून के लिए अज्ञात है. विद्वान एकल न्यायाधीश सुनवाई कर रहे थे दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील। अपीलीय की शक्तियाँ ,जी कोर्ट, बरी किए जाने के आदेश की अपील में, गिनाए गए हैं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 386(ए) में। वे शक्तियाँ इस बात पर विचार नहीं करतीं कि एक अपीलीय - न्यायालय, के बाद दोषसिद्धि दर्ज करते हुए, मामले को ट्रायल कोर्ट में भेजा जा सकता है सजा का उचित आदेश पारित करना। का न्यायिक कार्य उचित सज़ा लगाने का कार्य केवल द्वारा ही किया जा सकता है अपीलीय न्यायालय जब दोषमुक्ति के आदेश को उलट देता है और नहीं किसी अन्य न्यायालय द्वारा संहिता की योजना को ध्यान में रखते हुए आपराधिक प्रक्रिया, 1973 के बाद इस न्यायालय का विचार है कि अधिनियम की धारा 138 के तहत

अपीलकर्ता को दोषी पाते हुए उचित सज़ा लगाने का न्यायिक विवेक नहीं हो सका के पक्ष में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय सुनाया गया है विद्वान मजिस्ट्रेट के तहत अपीलकर्ता को दोषी पाया गया अधिनियम की धारा 138 यह उच्च न्यायालय का बाध्य कर्तव्य था तथ्यों के अनुरूप उचित सजा देना मामले का इसलिए, हम इसका अनुमोदन या स्वीकार नहीं करते हैं उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया चाहे जो भी हो, इसमें मामले में, हमने पाया है कि दोषमुक्ति को उलटना स्वयं नहीं था न्याय हित।

14. उपरोक्त कारणों से अपील स्वीकार की जाती है। द्वारा प्रस्तुत निर्णय एवं आदेश दिनांक 23 नवम्बर 2006 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश 2004 की आपराधिक अपील संख्या 946 एसबीए में चंडीगढ़ में अधिनियम की धारा 138 के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराना तय है एक तरफ और 6 दिसंबर 2003 का फैसला सुनाया गया विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कमल फौजदारी में, अपीलकर्ता को बरी करने वाली शिकायत संख्या 178/2001 को बहाल किया जाता है।

बी.बी.बी. अपील की अनुमति

डिस्कलेमर - यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कनिष्का ऋषि (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।